Regarding OBC reservation in Jharkhand

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : सभापति महोदय, पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी और विपक्ष जातिगत जनगणना की बात कर रहा है। पिछड़ों के साथ वर्षों से अन्याय होता रहा है । माननीय प्रधान मंत्री जी जब देश के पहले पिछड़े प्रधान मंत्री बने, तो उन्होंने ओबीसी आयोग की स्थापना की और उसको संवैधानिक दर्जा दिया । जिस तरह से एससी आयोग है, एसटी आयोग है, उसी तरह से अब ओबीसी आयोग है ।

सभापति महोदय, आप झारखंड में प्रभारी भी रहे हैं । पूरे देश में ओबीसी के लिए 27 पर्सेंट रिजर्वेशन है । लेकिन, झारखंड में केवल और केवल 14 पर्सेंट आरक्षण है, जिसके कारण पिछड़ा समाज परेशान है । कई ऐसी जातियां हैं, जो शेड्यूल ट्राइब्स में होनी चाहिए थीं, लेकिन ओबीसी कोटे में दे दिया, जैसे खेतौड़ी और घटवाल । मैं वर्षों से मांग कर रहा हूं खेतौड़ी और घटवाल को एसटी में डालिए, जिससे ओबीसी का हक नहीं मारा जाए । आज तक वहां की सरकार ने किसी प्रकार का कोई प्रपोजल न भारत सरकार को भेजा है और न ही ओबीसी को रिजर्वेशन मिला है ।

आज सभी जगह ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत रिजर्वेशन है और जातिगत जनगणना की बात हो रही है, लेकिन कांग्रेस सोशियो-इकोनॉमिक सेंसस को लागू नहीं करना चाहती है । कर्नाटक में कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद वहां की सरकार न उसे डिसक्लोज कर रही है और न लागू कर रही है। मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह है कि कांग्रेस और जेएमएम के ऊपर दबाव डाला जाए और किसी भी कीमत पर झारखंड में ओबीसी को 27 पर्सेंट रिजर्वेशन दिया जाए । मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से यह आग्रह है ।